

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023—वैशाख 22, शक 1945

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2023

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर 2022 तक (03 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 तथा 11 दिसम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

**कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 मार्च 2023

क्रमांक/1514/एफ-14/06/IGKV/2021/14-2.—विभागीय आदेश क्र. 6474, दिनांक 24-12-2021 द्वारा कृषि महाविद्यालय, साजा का नाम “स्व. कुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय कृषि महाविद्यालय, साजा” के नाम पर किया गया था. माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में प्राप्त अनुमोदन के परिपेक्ष्य में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कृषि महाविद्यालय, साजा का नाम “कुमारी देवी चौबे शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा, जिला बेमेतरा” किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2023

क्रमांक/1555/एफ-14/14/IGKV/2022-23/14-2.—विभागीय आदेश क्र. 3876, दिनांक 13-06-2022 द्वारा कृषि महाविद्यालय, ढोलिया, बेमेतरा का नाम “स्व. रेवेन्द्र सिंह वर्मा” के नाम पर किया गया था. माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में प्राप्त अनुमोदन के परिपेक्ष्य में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कृषि महाविद्यालय, ढोलिया, बेमेतरा का नाम “रेवेन्द्र सिंह वर्मा, कृषि महाविद्यालय, ढोलिया, जिला-बेमेतरा” किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. सी. पैकरा**, संयुक्त सचिव.

**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-5/2023/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

**अनुसूची-1**

नगर पंचायत पामगढ़ की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	ग्राम पंचायत पामगढ़	6064

**अनुसूची-2**

नगर पंचायत पामगढ़ की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :—

ग्राम पंचायत पामगढ़ की सीमाएं ही नगर पंचायत पामगढ़ की सीमाएं होंगी.

अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-जांजगीर चांपा को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. एक्का**, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-5/2023/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2023/18 दिनांक 06-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 11th April 2023

No. F 1-5/2023/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Pamgarh as Nagar Panchayat Pamgarh in District-Janjgir-Champa as per the Schedule given below :—

Schedule-1

The particulars of areas of Gram panchayat to be included in the limits of Nagar Panchayat Pamgarh is as under :—

S. No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Gram panchayat Pamgarh	6064

Schedule-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Pamgarh is as under :—

The Boundaries of the Nagar Panchayat Pamgarh shall be the boundaries of Gram Panchayat Pamgarh.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Janjgir-Champa on any official day and time within 15 days from the date of Publication in “Chhattisgarh Rajpatra” for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R. EKKA, Joint Secretary.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 मार्च 2023

क्रमांक 581/738/2011/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा श्री जे.आर. नायक, भा.व.से. (2001) मुख्य वन संरक्षक, रायपुर, वृत्त रायपुर, को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मार्च 2023

क्रमांक एफ 9-4/2014/38-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17-01-2023 द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23(एक-अ) के प्रावधान अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान मण्डल के पांच माननीय सदस्यों को मनोनीत किया गया था।

2. उक्त आदेश के सरल क्रमांक 1 पर मनोनीत माननीय श्री संत राम नेताम, सदस्य विधानसभा के छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री संत राम नेताम के स्थान पर माननीया श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा, पता-ग्राम-मु.पो.-फरसपाल, “सरपंचपारा” तहसील-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.) को “शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर” की कार्यपरिषद् में सदस्य के रूप में मनोनीत करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. आर. खान, अवर सचिव.**

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT MANTRALAYA  
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar (C.G.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्रमांक 4272/856/21-ब/छ.ग./2023.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-7 की उपधारा (1) (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एवं पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, एतद्वारा, राज्य में संलग्न अनुसूची के खण्ड (3) में दर्शित राजस्व जिलों को शामिल करते हुए खण्ड (2) में दर्शित निम्नानुसार सत्र खण्ड घोषित करता है, अर्थात :-

**अनुसूची**

स. क्र. (1)	सत्र खण्ड (जिला) (2)	सत्र खण्ड में शामिल राजस्व जिला (3)
1.	बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर-रामानुजगंज
2.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
3.	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार-भाटापारा
4.	बालोद	बालोद
5.	बेमेतरा	बेमेतरा
6.	बिलासपुर	(i) बिलासपुर (ii) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	(i) दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) (ii) बीजापुर (iii) सुकमा
8.	धमतरी	धमतरी
9.	दुर्ग	दुर्ग
10.	जांजगीर-चांपा*	(i) जांजगीर-चांपा (ii) सक्ती
11.	जशपुर	जशपुर
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)

(1)	(2)	(3)
13.	कोण्डागांव	(i) कोण्डागांव (ii) नारायणपुर
14.	कोरबा	कोरबा
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर) *	(i) कोरिया (बैकुण्ठपुर) (ii) मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
16.	महासमुंद	महासमुंद
17.	मुंगेली	मुंगेली
18.	रायगढ़ **	(i) रायगढ़ (ii) सारंगढ़-बिलाईगढ़
19.	रायपुर	(i) रायपुर (ii) गरियाबंद
20.	राजनांदगांव **	(i) राजनांदगांव (ii) मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी (iii) खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई
21.	सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
22.	सूरजपुर	सूरजपुर
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)

**टीप :—** \*सत्र खण्ड जांजगीर-चांपा में राजस्व जिला सक्ती एवं सत्र खण्ड कोरिया (बैकुण्ठपुर) में राजस्व जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर दिनांक 08-09-2022 से शामिल होंगे.

\*\*सत्र खण्ड रायगढ़ में राजस्व जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव में राजस्व जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई दिनांक 01-09-2022 से शामिल होंगे.

No. 4272/856/XXI-B/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (3) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications, the State Government in consultation with the High Court, hereby, declares that there shall be following Sessions Division shown in column (2) comprising of Revenue Districts, as shown in column (3), of the Schedule, in the State, namely :—

#### SCHEDULE

S. No.	Sessions Divisions (District)	Revenue District included in the Sessions Division
(1)	(2)	(3)
1.	Balrampur-Ramanujganj	Balrampur-Ramanujganj
2.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar (Jagdalpur)
3.	Balodabazar-Bhatapara	Balodabazar-Bhatapara
4.	Balod	Balod
5.	Bemetara	Bemetara
6.	Bilaspur	(i) Bilaspur (ii) Gourela-Pendra-Marwahi
7.	Dakshin Bastar (Dantewada)	(i) Dakshin Bastar (Dantewada) (ii) Bijapur (iii) Sukma
8.	Dhamtari	Dhamtari
9.	Durg	Durg
10.	Janjgir-Champa*	(i) Janjgir-Champa (ii) Sakti
11.	Jashpur	Jashpur

(1)	(2)	(3)
12.	Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)
13.	Kondagaon	(i) Kondagaon (ii) Narayanpur
14.	Korba	Korba
15.	Koria (Baikunthpur)*	(i) Koria (Baikunthpur) (ii) Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
16.	Mahasamund	Mahasamund
17.	Mungeli	Mungeli
18.	Raigarh **	(i) Raigarh (ii) Sarangarh-Bilaigarh
19.	Raipur	(i) Raipur (ii) Gariaband
20.	Rajnandgaon**	(i) Rajnandgaon (ii) Mohla-Manpur-Ambagarh-Chouki (iii) Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
21.	Sarguja (Ambikapur)	Sarguja (Ambikapur)
22.	Surajpur	Surajpur
23.	Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar (Kanker)

**Note :—** \*Merger of Revenue District Sakti into Sessions Division Janjgir-Champa and Merger of Revenue District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur into Sessions Division Koria (Baikunthpur) shall be with effect from 08-09-2022.

\*\*Merger of Revenue District Sarangarh-Bilaigarh into Sessions Division Raigarh and Merger of Revenue Districts Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki and Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai into Sessions Division Rajnandgaon shall be with effect from 01-09-2022.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्रमांक 4274/856/21-ब/छ.ग./2023.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एवं पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, एतद्वारा, राज्य में संलग्न अनुसूची के खण्ड (3) में दर्शित राजस्व जिलों को शामिल करते हुए खण्ड (2) में दर्शित निम्नानुसार सिविल जिले घोषित करता है, अर्थात :-

### अनुसूची

स. क्र. (1)	सिविल जिला (2)	राजस्व जिला (3)
1.	बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर-रामानुजगंज
2.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
3.	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार-भाटापारा
4.	बालोद	बालोद
5.	बेमेतरा	बेमेतरा
6.	बिलासपुर	(i) बिलासपुर (ii) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	(i) दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) (ii) बीजापुर (iii) सुकमा
8.	धमतरी	धमतरी
9.	दुर्ग	दुर्ग

(1)	(2)	(3)
10.	जांजगीर-चांपा*	(i) जांजगीर-चांपा (ii) सक्ती
11.	जशपुर	जशपुर
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
13.	कोण्डागांव	(i) कोण्डागांव (ii) नारायणपुर
14.	कोरबा	कोरबा
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)*	(i) कोरिया (बैकुण्ठपुर) (ii) मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
16.	महासमुंद	महासमुंद
17.	मुंगेली	मुंगेली
18.	रायगढ़**	(i) रायगढ़ (ii) सारंगढ़-बिलाईगढ़
19.	रायपुर	(i) रायपुर (ii) गरियाबंद
20.	राजनांदगांव**	(i) राजनांदगांव (ii) मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी (iii) खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई
21.	सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
22.	सूरजपुर	सूरजपुर
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)

**टीप :-** \*सिविल जिला जांजगीर-चांपा में राजस्व जिला सक्ती एवं सिविल जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) में राजस्व जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर दिनांक 08-09-2022 से शामिल होंगे.

\*\*सिविल जिला रायगढ़ में राजस्व जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं सिविल जिला राजनांदगांव में राजस्व जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई दिनांक 01-09-2022 से शामिल होंगे.

No. 4274/856/XXI-B/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications, the State Government on the recommendation of the High Court, hereby, declares there shall be following Civil Districts as shown in column (2) comprising of Revenue Districts as shown in column (3), of the Schedule, in the State, namely :—

#### SCHEDULE

S. No. (1)	Civil District (2)	Revenue District (3)
1.	Balrampur-Ramanujganj	Balrampur-Ramanujganj
2.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar (Jagdalpur)
3.	Balodabazar-Bhatapara	Balodabazar-Bhatapara
4.	Balod	Balod
5.	Bemetara	Bemetara
6.	Bilaspur	(i) Bilaspur (ii) Gourela-Pendra-Marwahi
7.	Dakshin Bastar (Dantewada)	(i) Dakshin Bastar (Dantewada) (ii) Bijapur (iii) Sukma
8.	Dhamtari	Dhamtari
9.	Durg	Durg

(1)	(2)	(3)
10.	Janjgir-Champa*	(i) Janjgir-Champa (ii) Sakti
11.	Jashpur	Jashpur
12.	Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)
13.	Kondagaon	(i) Kondagaon (ii) Narayanpur
14.	Korba	Korba
15.	Koria (Baikunthpur)*	(i) Koria (Baikunthpur) (ii) Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
16.	Mahasamund	Mahasamund
17.	Mungeli	Mungeli
18.	Raigarh **	(i) Raigarh (ii) Sarangarh-Bilaigarh
19.	Raipur	(i) Raipur (ii) Gariaband
20.	Rajnandgaon**	(i) Rajnandgaon (ii) Mohla-Manpur-Ambagarh-Chouki (iii) Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
21.	Sarguja (Ambikapur)	Sarguja (Ambikapur)
22.	Surajpur	Surajpur
23.	Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar (Kanker)

**Note :—** \*Merger of Revenue District Sakti into Civil District Janjgir-Champa and Merger of Revenue District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur into Civil District Koria (Baikunthpur) shall be with effect from 08-09-2022.

\*\*Merger of Revenue District Sarangarh-Bilaigarh into Civil District Raigarh and Merger of Revenue Districts Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki and Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai into Civil District Rajnandgaon shall be with effect from 01-09-2022.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary.

### गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 7-06/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सुजीत कुमार, (भापुसे-2010), सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सूरजपुर, छ.ग. को दिनांक 18 मई 2023 से 26 मई 2023 (कुल 09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 27 एवं 28 मई 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुजीत कुमार आगामी आदेश तक सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सूरजपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री सुजीत कुमार को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुजीत कुमार (भापुसे-2010) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

5. श्री सुजीत कुमार (भापुसे-2010), सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सूरजपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी.पी. राजभानू, (भापुसे-2010), सेनानी, 12वीं वाहिनी, छसबल, रामानुजगंज, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.



**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10659/भू-अर्जन/2022.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी	4.18 एकड़	कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-10-2022 को समय 12.00 बजे स्थान पंचायत भवन कनबेरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3179.12 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय निस्तार एवं भू-जल संवर्धन इत्यादि होगा. परियोजना से कुल 03 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कुल 03 ग्राम में जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेयजल की समस्या हल होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजीव कुमार झा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

जशपुर, दिनांक 24 मार्च 2023

**प्ररूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/189/वाचक/भू-अर्जन/2023.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
जशपुर	फरसाबहार	लठबोरा	1.179 हेक्टेयर	लठबोरा से सुईजोर सड़क व पुलिया निर्माण मार्ग लंबाई 3.53 कि.मी. का कार्य.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-11-2022 को ग्राम पंचायत लठबोरा के ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लठबोरा से सुईजोर सड़क व पुलिया निर्माण मार्ग लंबाई 3.53 कि.मी. का कार्य.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	13
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	624.76 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन सुदृढ़ होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

जशपुर, दिनांक 24 मार्च 2023

**प्ररूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/190/वाचक/भू-अर्जन/2023.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
जशपुर	फरसाबहार	सुईजोर	0.623 हेक्टेयर	लठबोरा से सुईजोर सड़क व पुलिया निर्माण मार्ग लंबाई 3.53 कि.मी. का कार्य.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-11-2022 को ग्राम पंचायत लठबोरा के ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लठबोरा से सुईजोर सड़क व पुलिया निर्माण मार्ग लंबाई 3.53 कि.मी. का कार्य.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	624.76 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन सुदृढ़ होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रवि मित्तल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2023

क्रमांक 202201031700027/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	दुलदुला	कोमड़ो प.ह.नं. 13	2.979	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	चम्पाझरिया व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर चै.क्र. 133 से 191.50 तक 17 वृक्षों सहित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 मार्च 2023

क्रमांक/194/A/वाचक/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
जशपुर	फरसाबहार	लठबोरा	1.179	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जशपुर.		लठबोरा से सुईजोर सड़क व पुलिया निर्माण मार्ग लंबाई 3.53 कि.मी. भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), फरसाबहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 मार्च 2023

क्रमांक/195/A/वाचक/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	सुईजोर	0.623	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जशपुर.	लठबोरा से सुईजोर सड़क व पुलिया निर्माण मार्ग लंबाई 3.53 कि.मी. भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), फरसाबहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 28 मार्च 2023

क्रमांक 116/202010141400004/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	कुलगांव प.ह.नं. 33	0.578	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण कांकेर.	सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

मोहला-मानपुर-अं.चौकी, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक/2257/20221030030012/अ-82/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोहला-मानपुर- अं.चौकी	अं. चौकी	करमतरा प.ह.नं. 23	0.145	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	बिहरीकला -दनगढ़- गोटाटोला मार्ग में दनगढ़ नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के न्यायालय में किया जा सकता है.

मोहला-मानपुर-अं.चौकी, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक/2258/202209300300002/अ-82/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोहला-मानपुर- अं.चौकी	अं. चौकी	दोड़के प.ह.नं. 22	0.466	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, दुर्ग.	दोड़के-विचारपुर मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के न्यायालय में किया जा सकता है.

मोहला-मानपुर-अं.चौकी, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक/2259/202210300300001/अ-82/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोहला-मानपुर-अं.चौकी	मोहला	दनगढ़ प.ह.नं. 17	0.750	कार्यपालन परियोजना, प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि., राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग.	बिहरीकला -दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला-खडगांव मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 27 अप्रैल 2023

क्रमांक/6021/202112050400034/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	ढेलवाडीह प.ह.नं. 09	0.071	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर.	ढेलवाडीह-पतरापाली मार्ग में अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 अप्रैल 2023

क्रमांक/6026/202109050500009/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कुचैना प.ह.नं. 39	0.615	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर.	कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा - अकलतरा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 अप्रैल 2023

क्रमांक/6029/202109050500008/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	दर्दी	भैरोताल प.ह.नं. 40	0.259	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर.	कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा - अकलतरा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 14 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3350/20/अ-82/2017-18.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा  
(ख) तहसील-कटघोरा  
(ग) नगर/ग्राम-धवईपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.120 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655/2	0.113
658/2	0.073
660	0.061
658/1	0.036
641	0.065
655/1	0.145
661/1	0.073
642/1क	0.020
642/1ख	0.069
642/2	0.008
643/1	0.036
624	0.020
626/2	0.045
697/2	0.016
698/2, 699/1	0.008
698/3	0.045
698/5	0.069
692/1	0.028
692/2	0.040
697/1 में से	0.024

(1) (2)

700/1 में से	0.073
663/1, 663/2, 663/3	0.049
656/1	0.004

योग 23 1.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा  
व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3353/38/अ-82/2017-18.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा  
(ख) तहसील-कटघोरा  
(ग) नगर/ग्राम-हराभाठा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236	0.069
228	0.065
227/1	0.036
239/1	0.037
239/2	0.016
239/4	0.020
164/6	0.057
164/4	0.040
164/9	0.008
255	0.061

(1)	(2)
256	0.165
271	0.093
164/10	0.020
269/3	0.105
270	0.145
272	0.008
278/1	0.036
278/2	0.040
276/6	0.040
251/3	0.063
251/1	0.024
241/3	0.004
251/2	0.003
227/2	0.226
276/2क	0.036
276ख	0.045
276/5	0.048
241/1	0.016
योग	28
	1.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा  
व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3356/07/अ-82/2017-18.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई  
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में  
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि  
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता  
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,  
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित  
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता  
है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-भेजीनारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.215 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
210/9	0.210
210/8क	0.263
210/8/ख	0.041
210/6/क	0.263
210/6/ख	0.243
210/26क	0.121
210/27क	0.405
202/2	0.142
210/26ख	0.122
210/27ख	0.405
योग	10
	2.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोलारनाला  
स्टाप डेम क्र. 02 के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3359/43/अ-82/2017-18.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई  
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में  
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि  
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता  
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,  
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित  
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता  
है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-शुक्लाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.742 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147/2	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
151/1च/1	0.040	237/3	0.097
151/1च/2	0.040	240/1ख	0.041
151/1च/3	0.040	240/1ग	0.016
151/1च/4	0.040	239/1	0.008
147/1, 141/1, 146/1, 152/3	0.053	264/2	0.073
151/2	0.016	264/1	0.101
1/15	0.085	259/2	0.041
135/4	0.016	260	0.024
135/7	0.165	141/2, 146/2, 147/3, 152/5	0.049
135/8	0.133	151/5	0.081
135/1	0.129	131	0.008
135/5	0.109	263/5	0.032
123/1	0.165	133/5	0.008
126	0.028	133/7	0.008
90/1, 89	0.085	133/6	0.008
91/2	0.109	240/1क	0.113
122/1/ख	0.049	240/1घ	0.117
122/2	0.016	239/2	0.008
92	0.008	235/2	0.032
122/1/क	0.194	56/1क	0.206
87/4	0.008	151/6	0.105
88/1, 170/1, 171, 183	0.061	133/1	0.040
87/3	0.024	133/2	0.008
169, 170/2	0.016	133/3	0.008
183/3/ख	0.089	133/4	0.008
87/5	0.032	133/8	0.008
75/1ख	0.053	133/9	0.008
56/1ग	0.057	132/1	0.101
128/2	0.053	127/2	0.113
120/3	0.105	149	0.073
209/1	0.028	132/2	0.121
210	0.085	211/2	0.032
237/2	0.061	216	0.053
86/2	0.020		
209/2	0.028	योग	79
237/4	0.153		4.742
86/3	0.020		
203/8	0.081	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा	
203/4	0.061	व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
203/1	0.268	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
211/4	0.041	(रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
203/10	0.008		
211/5	0.085	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
		संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,	(1)	(2)
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,		
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	345/2	0.022
	345/4	0.010
उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 12 अप्रैल 2023	345/3	0.020
क्रमांक/130/वा./भू.अ./प्र.क्र./202110141400001/अ-82/	346	0.034
21-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि	347	0.060
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद	407	0.230
(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः	408	0.083
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और	409	0.098
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्	412	0.050
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा	413	0.044
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए		
आवश्यकता है :—		
अनुसूची		
	योग	
	11	0.669
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिचरी-	
(ख) तहसील-नरहरपुर	चारभाठा मार्ग के सलेरिया नदी पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण	
(ग) नगर/ग्राम-चारभाठा	हेतु.	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.669 हेक्टेयर	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
	(रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा	
	सकता है.	
खसरा नम्बर	रकबा	
	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
345/1	0.018	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्रमांक/106/भू.अ./अ.भू.अ./2023.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्र. 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय-7 की धारा 68, 69, 70, 72, 73 एवं सह पठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं डोमन सिंह, कलेक्टर जिला राजनांदगांव एतद्द्वारा तहसील छुरिया, राजस्व निरीक्षक मंडल-उमरवाही, पटवारी हल्का नंबर 52 के राजस्व ग्राम कारूटोला को राजस्व ग्राम अधिसूचित करता हूं.

क्र.	भूमि मदवार	ग्राम कारूटोला
(1)	(2)	(3)
1.	ग्राम का रकबा	194.375 हे.
2.	खाते का रकबा	49.165 हे.

(1)	(2)	(3)
3.	गैर खाता एवं निस्तार का रकबा	5.650 हे.
4.	जनसंख्या	150 हे.
5.	मवेशी संख्या	125 हे.
6.	आबादी भूमि	4.921 हे.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्रमांक/107/भू.अ./अ.भू.अ./2023.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्र. 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय-7 की धारा 68, 69, 70, 72, 73 एवं सह पठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं डोमन सिंह, कलेक्टर जिला राजनांदगांव एतद्वारा तहसील छुरिया, राजस्व निरीक्षक मंडल-कुमरदा, पटवारी हल्का नंबर 35 के राजस्व ग्राम हटोईटोला को राजस्व ग्राम अधिसूचित करता हूँ.

क्र. (1)	भूमि मदवार (2)	ग्राम हटोईटोला (3)
1.	ग्राम का रकबा	92.366 हे.
2.	खाते का रकबा	32.659 हे.
3.	गैर खाता एवं निस्तार का रकबा	59.707 हे.
4.	जनसंख्या	—
5.	मवेशी संख्या	—
6.	आबादी भूमि	—

डोमन सिंह,  
कलेक्टर

### कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2023

क्रमांक/260/भू.अभि./रा.नि./2023.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (राजस्व ग्राम के छोटे असर्वेक्षित भूमि) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :-

क्र. (1)	जिला का नाम (2)	तहसील (3)	प.ह.नं. (4)	ग्राम का नाम (5)	रिमार्क (6)
1.	जशपुर	पत्थलगांव	09	पालीडीह	434273

No. 260/L.R./R.I./2023.—In exercise of powers conferred by Sub section (1) of Section 67 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, (No. 20 of 1959), The District Survey Officer, hereby, is pleased to declare initiation of the revenue survey operation in the area specified in the schedule (Userved Land of revenue village) as given below. This area shall be held to be under such survey from the date of notification until the issue of a notification declaring the operation to be closed :—

## SCHEDULE

S.No. (1)	District Name (2)	Tehsil (3)	P.H. No. (4)	Name of Village (5)	Remark (6)
1.	Jashpur	Pathalgaon	09	Palidih	434273

रवि मित्तल,  
जिला सर्वेक्षण अधिकारी.

## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2023

क्रमांक/627/कले./अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./2023.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4680/2017/आ.भू.अ./स्था-2/नया रायपुर दिनांक 29-11-2017 द्वारा राजस्व निरीक्षक के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप राजस्व निरीक्षक मंडल की पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश अनुरूप छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए मैं डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर जिला रायपुर एतद्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजस्व निरीक्षक मंडल के पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ.

स. क्र.	तहसील	वर्तमान रा.नि.म.	नवीन प्रस्तावित रा.नि.म.	सम्मिलित पटवारी हल्का व नाम	पटवारी हल्का में सम्मिलित ग्राम	खाता संख्या	भौगोलिक क्षेत्रफल	ग्राम पंचायत	
1	रायपुर	रायपुर-18 कांदुल	सेरीखड़ी	14, तुलसी	संकरी	2006	580.764		
2					तुलसी	1034	713.976	तुलसी	
3					15, पिरदा	पिरदा	2343	568.283	पिरदा
4					16, सेरीखड़ी	नकटी	796	431.657	
5						सेरीखड़ी	1557	898.640	सेरीखड़ी
6					39, टेमरी	धरमपुरा	1695	971.619	
7						टेमरी	3174	448.977	टेमरी
8					40, बनरसी	बनरसी	3141	468.998	बनरसी
	योग			5	8	15746	5082.914		
9	रायपुर	रायपुर-18 कांदुल	कांदुल 18	51, माना	माना	3516	1068.241	माना	
10					भटगांव	1084	317.625		
11					50, बोरियाकला	बोरियाकला	5260	1052.982	बोरियाकला
12						धनेली	1274	432.079	
13					49, सेजबहार	सेजबहार	4697	680.058	सेजबहार
14						मुजगहन	1008	324.315	
15					47, कांदुल	काठाडीह	1055	277.841	
16						कांदुल	2847	453.000	कांदुल
17					48, डोमा	दतरंगा	2334	567.639	दतरंगा
18						डोमा	1998	419.051	
	योग			5	10	25073	5592.831		

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल पुनर्गठन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को दावा आपत्ति हो, तो दिनांक 03-05-2023 सांय 5.00 बजे तक कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा. प्राप्त दावा आपत्ति की सुनवाई दिनांक 04-05-2023 को समय 3.00 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में की जावेगी.

सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे,  
कलेक्टर.

### कार्यालय कलेक्टर ( भू-अभिलेख शाखा ) जिला-बेमेतरा ( छ.ग. )

बेमेतरा, दिनांक 13 अप्रैल 2023

#### उद्घोषणा

क्रमांक 314/भू.अभि./अ.भू.अ./2023.—मैं पदुम सिंह एल्मा, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, ग्राम पतौरा, प.ह.नं. 08, तहसील थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा के बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67(1), (3)(घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रस्थापित भू-सर्वेक्षण किये जाने अधिसूचित करता हूं.

पदुम सिंह एल्मा,  
कलेक्टर.

### उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 25/L.G./2023/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days from 02-02-2023 to 06-02-2023 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 01-02-2023 till before the office hours 07-02-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 26/L.G./2023/II-3-28/2009.—Shri Santosh Kumar Aditya, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 15-02-2023 to 17-02-2023 along with permission to remain out of headquarters from 15-02-2023 to 18-02-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Aditya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 259 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 27/L.G./2023/II-3-14/2014.—Ms. Sanghratna Bhatpahari, Special Judge (Atrocities), Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 28-12-2022 to 31-12-2022 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 till before the Court hours of, 02-01-2023 and earned leave for 06 days from 30-01-2023 to 04-02-2023 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 29-01-2023 till before the Court hours of 06-12-2023.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Ms. Bhatpahari, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 28/L.G./2023/II-2-19/2019.—Smt. Dhaneshwari Sidar, Judge, Family Court, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 01 day on 31-12-2022 in continuation of winter Vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 to 01-01-2023 and earned leave for 06 days from 30-01-2023 to 04-02-2023 along with permission to remain out of headquarters from 29-01-2023 to 05-02-2023.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sidar, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 29/L.G./2023/II-2-30/2017.—Shri Khilawan Ram Rigri, Special Judge (Atrocities), Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 05 days from 31-01-2023 to 04-02-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 30-01-2023 till before the Court hours of 06-02-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rigri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.



Bilaspur, the 1st March 2023

No. 30/L.G./2023/II-2-20/2019.—Shri Thomas Ekka, Special Judge (Atrocities), Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-02-2023 to 10-02-2023 along with permission to remain out of headquarters from 01-02-2023 till before the Court hours of 13-02-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 147 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 31/L.G./2023/II-2-97/2007.—Shri Suresh Kumar Soni, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-02-2023 to 10-02-2023 along with permission to remain out of headquarters from 01-02-2023 to 12-02-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Soni, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)

---